



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 182]
No. 182]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 29, 2003/श्रावण 7, 1925
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 29, 2003/SRAVANA 7, 1925

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2003

**विषय :—इंडोनेशिया, मलेशिया तथा यू ए ई से थर्मल सेंसेटिव पेपर के आयात से संबंधित
पाटन रोधी जाँच की शुरूआत।**

सं. 14/2/2003/डी जी ए डी.—सन् 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क अधिनियम 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनपर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम 1995 के अनुसार मैसर्स श्री कृष्णा पेपर मिल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया तथा यू ए ई के मूल के या वहाँ से निर्यातित थर्मल सेंसेटिव पेपर के पाटन का आरोप लगाया है तथा पाटनरोधी जाँच आरंभ करने तथा पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

विचाराधीन उत्पाद

2. वर्तमान याचिका में शामिल उत्पाद थर्मल सेंसेटिव पेपर (टी एस पी) है (जिसे इसके बाद संबद्ध वस्तु कहा गया है) । थर्मल सेंसेटिव पेपर एक ऐसा पेपर है जसमें रसायनों के एक विशेष मिश्रण का लेप चढ़ाया गया होता है जो बेस पेपर को थर्मल सेंसेटिव गुण प्रदान करता है। पेपर पर नियंत्रित थर्मल ताप देकर पेपर पर छाप बनायी जाती है। थर्मल सेंसेटिव पेपर का प्रयोग मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक उपस्करों के लिए संदेश रिकार्ड करने हेतु किया जाता है, जहाँ मशीन का प्रयोग संदेश रिकार्ड करने के लिए किया जाता है वहाँ उष्मा की किरणों की संवेदनशीलता के द्वारा यह कार्य होता है। वहाँ उष्मा किरणों की संवेदनशीलता के द्वारा यह कार्य होता है। थर्मल सेंसेटिव पेपर मुख्यतः फैक्स मशीनों में प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग इ सी जी मशीनों तथा अन्य चिकित्सा उपस्करों, सीम्सोग्राफिक मशीनों, एयरलाइन्स बैगेज टैगिंग, टिकट बोर्डिंग कार्ड इत्यादि में भी होता है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि टी एस पी सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 48 के अंतर्गत वर्गीकृत है। उत्पाद का कोई विशिष्ट वर्गीकरण नहीं है।

तथापि यह सामान्यतः उपशीर्ष 4809.10 अर्थात् "कार्बन या इसी प्रकार का कोयला पेपर" के अंतर्गत आता है। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया है कि टी एस सी सीमाशुल्क टैरिफ वर्गीकरण के शीर्ष 4811 तथा 4816 के विभिन्न उपशीर्षों के भी अंतर्गत आता है यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के क्षेत्र पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

घरेलू उद्योग

3. याचिका मैसर्स श्री कृष्णा पेपर मिल्स तथा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि वह भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है तथा अतः पूर्वोक्त नियमावली के नियम 5(3) (क) के अनुसार वह घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने के मानदंड को पूरा करता है।

शामिल देश

4. वर्तमान जांच में शामिल देश इंडोनेशिया, मलेशिया तथा यू ए ई हैं, जिन्हें इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है।

समान वस्तु

5. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उनके द्वारा विनिर्मित माल तथा इंडोनेशिया, मलेशिया तथा यू ए ई के मूल का अथवा वहाँ से निर्यातित माल समान वस्तुएँ हैं। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित माल को उपर्युक्त नियमावली के अर्थ के भीतर संबद्ध देश से आयातित माल के समान वस्तु माना जा रहा है।

सामान्य मूल्य

6. याचिकाकर्ता ने इंडोनेशिया, मलेशिया तथा यू ए ई के मामले में सामान्य मूल्य का दावा संबद्ध वस्तु के परिकलित सामान्य मूल्य के आधार पर किया है। संबद्ध देश के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के अनुमान के आधार पर किया गया है जिसमें बिक्री, सामान्य तथा प्रशासनिक, खर्च एवं उचित लाभ मार्जिन विधिवत रूप से समायोजित है।

निर्यात कीमत

7. याचिकाकर्ताओं ने संबद्ध देश से निर्यात कीमत का दावा गौण स्रोतों से एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर किया है। कारखाना द्वार स्तर पर निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़े, बीमा, कमीशन, संबद्ध देश में अन्तर्देशी परिवहन, पत्तन हैंडलिंग के लिए समायोजनों का दावा किया गया है।

पाटन मार्जिन

8. संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का निर्यात मूल्य, जिसका दावा भारत में संबद्ध वस्तु की परिकलित उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है जिसमें उचित सामान्य, प्रशासनिक खर्च तथा बिक्री लागत एवं लाभ भी जोड़े गये हैं, निवल निर्यात मूल्य से काफी अधिक है, जो प्रथम दृष्टया यह इंगित करता है कि संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

9. क्षति से संबंधित विभिन्न मापदंड यथा-उत्पादन, क्षमता उपयोग, रोजगार, मजदूरी लगाई पूंजी पर लाभ, नकद लाभ, मांग का बाजार हिस्सा, लाभ तथा हानि, बिक्री प्राप्ति में ह्रास, कीमत कटौती, कीमत कमी तथा ह्रास, क्षमता का अधिकतम से कम उपयोग, संबद्ध वस्तु की बिक्री से उचित कीमत नहीं प्राप्त करने के कारण घरेलू उद्योग को हुई हानि से प्रथम दृष्टया सामूहिक तथा सचंयी रूप से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

पाटनरोधी जाँच शुरू करना

10. पूर्ववर्ती पैराग्राफों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल के या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आरोपित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा और उसके प्रभाव की पाटनरोधी जाँच शुरू करते हैं।

जाँच की अवधि (पी ओ आई)

11. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जाँच की अवधि 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2003 तक है।

सूचना प्रस्तुत करना

12. संबद्ध देशों के निर्यातकों, तथा इस जाँच से संबंधित समझे जाने वाले भारत के ज्ञात आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है कि वे निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी तथा संबद्ध शुल्क महानिदेशालय, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110011 को संगत सूचना प्रस्तुत करें तथा अपने विचारों से अवगत कराएं।

समय सीमा

13. वर्तमान जाँच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप से भेजी जानी चाहिए जो उपर्युक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर पहुँच जानी चाहिए। तथापि जिन ज्ञात निर्यातकों तथा आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है वे अलग से भेजे गए पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर सूचना प्रस्तुत करें।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

14. नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं। यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है अथवा महत्वपूर्ण ढंग से जाँच में बाधा डालती है अथवा सूचना किसी भी रूप में अधूरी होती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING & ALLIED DUTIES****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th July, 2003

Subject :—Initiation of Anti-dumping investigation concerning import of Thermal Sensitive Paper from Indonesia, Malaysia and UAE.

No. 14/2/2003/DGAD.—M/s. Shree Krishna Paper Mills & Industries Limited, New Delhi have filed a petition in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) alleging dumping of Thermal Sensitive Paper originating in or exported from Indonesia, Malaysia and UAE and requested for Anti Dumping investigations and levy of anti dumping duties.

PRODUCT UNDER CONSIDERATION

2. The product involved in the present petition is Thermal Sensitive Paper (TSP) (hereinafter referred as subject goods). Thermal Sensitive Paper is a paper coated with a special mix of chemicals for providing thermal sensitive properties to the base paper. Impression on the paper is created by virtue of controlled thermal heat exposed on the paper. Thermal Sensitive Paper is primarily used for recording messages for electronic equipments where the machine is used to record messages, reports through sensitivity of heat rays. Thermal Sensitive Paper is primarily used in fax machines. It is also used in ECG Machines and other medical equipment's, Seismographic machines, Airlines baggage tagging, tickets, boarding cards etc. Petitioners have claimed that TSP is classified under chapter 48 of the Customs Tariff Act. The product does not have a dedicated Customs Classification. However, it generally gets covered under sub-heading 4809.10 i.e. 'Carbon or similar copying paper'. Petitioners have also claimed that TSP is also cleared under different sub-headings of heading 4811 and 4816 of the Customs Tariff Classification. These Classifications are indicative only and are in no way binding on the scope of the present investigation.

DOMESTIC INDUSTRY

3. The petition has been filed by M/s. Shree Krishna Paper Mills & Industries Limited, New Delhi. The petitioner has claimed that it is the only producer of the subject goods in India and therefore, satisfy the criteria of standing to file the petition on behalf of the domestic industry in terms of Rule 5(3)(a) of the Rules supra.

COUNTRIES INVOLVED

4. The countries involved in the present investigation are Indonesia, Malaysia and UAE hereinafter referred to as the subject countries.

LIKE ARTICLE

5. The petitioners have claimed that the goods produced by them are like articles to the goods produced, originating in or exported from Indonesia, Malaysia and UAE. Therefore, for the purpose of the present investigation, the goods produced by the petitioners are being treated as 'like articles' to that imported from the subject country within the meaning of the Rules supra.

NORMAL VALUE

6. The petitioner has claimed normal value based on the constructed normal value of subject goods in case of Indonesia, Malaysia and UAE. The normal value for subject countries has been constructed on the basis of estimates of cost of production of subject goods duly adjusted to include selling, general and administrative expenses and a reasonable profit margin.

EXPORT PRICE

7. The petitioners have claimed export price from the subject country based on the secondary data sources. Adjustments have been claimed on account of ocean freight, insurance, commission, inland transportation in subject countries, port handling to arrive at the Export Price at ex-factory level.

DUMPING MARGIN

8. The Normal Value of the subject goods in the subject countries, which is claimed on the basis of constructed cost of production of the subject goods in India with reasonable addition for general, administrative and selling cost and for profits, is significantly higher than the net export price indicating prima-facie that the subject goods are being dumped by exporters from the subject countries.

INJURY AND CAUSAL LINK

9. Various parameters relating to injury such as production, capacity utilization, employment, wages, return on capital employed, cash profit, market share in demand, profit & loss, decline in the sales realization, price undercutting, price suppression and price depression, sub-optimal utilization of capacity and losses to the Domestic Industry due to non-realization of fair and reasonable price from sale of the subject goods, prima-facie indicate collectively and cumulatively that the Domestic Industry has suffered material injury on account of dumping.

INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATIONS

10. The Designated Authority, in view of the foregoing paragraphs, initiates anti-dumping investigations into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

11. The period of investigation for the purpose of present investigation is 1st April 2002 to 31st March 2003.

SUBMISSION OF INFORMATION

12. The exporters in the subject countries and the importers in India known to be concerned with this investigation are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority, Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties, Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Government of India, Udyog Bhavan, New Delhi-110011. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

TIME LIMIT

13. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are however, required to submit the information within forty days from the date of the letter addressed to them separately.

INSPECTION OF PUBLIC FILE

14. In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority.